

विस चुनाव : अद्वैतिक बलों के 11 हजार जवानों की होगी तैनाती

खबर मन्त्र संवाददाता

अद्वैतिक बल की कितनी कंपनीयां होगी तैनाती
लॉन्चरफ़ : 43
सीआरपीएफ़ : 36
आईटीपीओ : 15
सीआइससैफ़ : 10
एसएसवी : 15
कुल : 119

रांची। झारखण्ड विधानसभा चुनाव की तीरीखों की घोषणा के बाद झारखण्ड पुलिस भी चुनाव की तैयारियों में जुट गयी है। पुलिस नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को लेकर फोकस कर रही है। निष्पक्ष चुनाव को लेकर झारखण्ड में 119 कंपनी (11 हजार जवान) अद्वैतिक बलों की तैनाती होगी। जिनमें से 91 अद्वैतिक बल की कंपनीयां शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया था तथा लोकसभा चुनाव झारखण्ड में लोकसभा चुनाव 2024 ने चुनाव आयोग से 590 कंपनी अद्वैतिक बल की मांग की थी। एक जिले में तीन से पांच कंपनी अद्वैतिक बल की होगी तैनाती है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर झारखण्ड पुलिस ने चुनाव आयोग से 590 कंपनी अद्वैतिक बल की मांग की थी। एक जिले में तीन से पांच कंपनी अद्वैतिक बल की होगी तैनाती है। हिंसा की साजिश को नाकाम कर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराया था। एक-एक जिला को मिल सकेगा। इन बलों को फैलेंगे मार्च, एरिया विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने की चुनौती है।

खबर मन्त्र व्यूप्ति एक नजर में

पंकज मिश्रा को हाई कोर्ट से मिली जमानत

रांची। साहिबगंज जिले में अवैध खनन और मनी लॉडिंग के आरोपी पंकज मिश्रा को सोमवार का हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। जरिसे गोरम कुमार वैधारी की अदालत ने फैसला सुनाते हुए जमानत प्रदान की है। जमानत मिलने के बाद पंकज मिश्रा जेल से बाहर आ जाएंगे। पूर्व में इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पूर्व पंकज मिश्रा ने ईडी कोट्टे में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। ईडी कोट्टे ने याचिका खारिज करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था। ईडी ने पंकज मिश्रा को जुर्माना 2022 में गिरफ्तार किया था।

सीडब्ल्यूसी के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार ने पांच साप्ताह का समय मांगा

रांची। राज्य में बाल संरक्षण आयोग एवं बाल कल्याण कमेटी (सीडब्ल्यूसी) के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार ने हाईकोर्ट से पांच साप्ताह का समय मांगा है। सोमवार को सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि बाल संरक्षण आयोग और सीडब्ल्यूसी के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया लाभग पूरी कर ली गयी है। मुख्यमंत्री से मंजूरी लेकर इसे निर्वाचन आयोग के पास भेजा जायेगा। इस पूरी प्रक्रिया में पांच साप्ताह का समय लग जायेगा। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई पांच साप्ताह बाद निर्धारित कर दी।

30 मई से निलंबित की गयीं साधना जयपुरियार

रांची। झारखण्ड प्रशासनिक सेवा की अधिकारी साधना जयपुरियार को तीन माह पहले की तिथि से निलंबित किया गया है। उनका निलंबन 30 मई 2024 की तिथि से अगले आदेश तक किया गया है। मालूम हो कि डीरी लातेहार ने 2 मई 2024 के प्रत्यक्ष से यह सूचित किया था कि मनिका कांड सख्त 76/2010 की सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने एक मामले में 30 मई 2024 की तिथि से तकालीन मनिका बीड़ीओं को तीन माह का सम्राट कारावास एवं 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी आलोक में कार्रिक पिंडियार के उहाँ निलंबित किया है।

विधानसभा चुनाव को लेकर रांची रेंज के डीआइजी ने स्किमडेंग में की इंटर स्टेट मीटिंग

रांची। विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा के इंतजारों का जायजा लेने रांची रेंज के डीआइजी अनुभा विरेश ने स्किमडेंग ऑडिशा और छोटीसगढ़ के पुलिस अधिकारियों के साथ इंटर स्टेट मीटिंग की। साथ ही कई अवधिक निर्देश दिए। डीआइजी ने स्किमडेंग एसपी सहित स्किमडेंग के पुलिस पदाधिकारी को चुनाव के दौरान सुरक्षा बरतने के लिए कई तरह बताया कि इन्होंने बताया कि इन्होंने चुनाव के दौरान सुरक्षित रख लिया था। इससे पूर्व पंकज मिश्रा ने ईडी कोट्टे में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। ईडी कोट्टे ने याचिका खारिज करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था। ईडी ने पंकज मिश्रा को जुर्माना 2022 में गिरफ्तार किया था।

पोटका में अर्जुन मुंडा ने किया जनसंवाद

रांची। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने सोमवार को पोटका विधानसभा क्षेत्र के द्वारा यारिया में बृहुत अध्यक्षों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि लोगों ने संकल्प लिया है कि इन वर्ष से चुनाव तक राज्य के आरोपी विधायिक विधायिक परिषद के अंतर्गत लगातार निर्वाचन आयोग के पास भेजा जायेगा। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई पांच साप्ताह बाद निर्धारित कर दी।

झारखण्ड के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार ने पांच साप्ताह का समय मांगा

रांची। राज्य में बाल संरक्षण आयोग एवं बाल कल्याण कमेटी (सीडब्ल्यूसी) के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार ने हाईकोर्ट से पांच साप्ताह का समय मांगा है। सोमवार को सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि बाल संरक्षण आयोग और सीडब्ल्यूसी के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया लाभग पूरी कर ली गयी है। मुख्यमंत्री से मंजूरी लेकर इसे निर्वाचन आयोग के पास भेजा जायेगा। इस पूरी प्रक्रिया में पांच साप्ताह का समय लग जायेगा। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई पांच साप्ताह बाद निर्धारित कर दी।

पोटका में अर्जुन मुंडा ने किया जनसंवाद

रांची। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने सोमवार को पोटका विधानसभा क्षेत्र के द्वारा यारिया में बृहुत अध्यक्षों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि लोगों ने संकल्प लिया है कि इन वर्ष से चुनाव तक राज्य के आरोपी विधायिक विधायिक परिषद के अंतर्गत लगातार निर्वाचन आयोग के पास भेजा जायेगा। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई पांच साप्ताह बाद निर्धारित कर दी।

झारखण्ड के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार ने पांच साप्ताह का समय मांगा

रांची। राज्य में बाल संरक्षण आयोग एवं बाल कल्याण कमेटी (सीडब्ल्यूसी) के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार ने हाईकोर्ट से पांच साप्ताह का समय मांगा है। सोमवार को सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि बाल संरक्षण आयोग और सीडब्ल्यूसी के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया लाभग पूरी कर ली गयी है। मुख्यमंत्री से मंजूरी लेकर इसे निर्वाचन आयोग के पास भेजा जायेगा। इस पूरी प्रक्रिया में पांच साप्ताह का समय लग जायेगा। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई पांच साप्ताह बाद निर्धारित कर दी।

झारखण्ड के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार ने पांच साप्ताह का समय मांगा

रांची। राज्य में बाल संरक्षण आयोग एवं बाल कल्याण कमेटी (सीडब्ल्यूसी) के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार ने हाईकोर्ट से पांच साप्ताह का समय मांगा है। सोमवार को सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि बाल संरक्षण आयोग और सीडब्ल्यूसी के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया लाभग पूरी कर ली गयी है। मुख्यमंत्री से मंजूरी लेकर इसे निर्वाचन आयोग के पास भेजा जायेगा। इस पूरी प्रक्रिया में पांच साप्ताह का समय लग जायेगा। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई पांच साप्ताह बाद निर्धारित कर दी।

झारखण्ड के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार ने पांच साप्ताह का समय मांगा

रांची। राज्य में बाल संरक्षण आयोग एवं बाल कल्याण कमेटी (सीडब्ल्यूसी) के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार ने हाईकोर्ट से पांच साप्ताह का समय मांगा है। सोमवार को सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि बाल संरक्षण आयोग और सीडब्ल्यूसी के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया लाभग पूरी कर ली गयी है। मुख्यमंत्री से मंजूरी लेकर इसे निर्वाचन आयोग के पास भेजा जायेगा। इस पूरी प्रक्रिया में पांच साप्ताह का समय लग जायेगा। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई पांच साप्ताह बाद निर्धारित कर दी।

झारखण्ड के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार ने पांच साप्ताह का समय मांगा

रांची। राज्य में बाल संरक्षण आयोग एवं बाल कल्याण कमेटी (सीडब्ल्यूसी) के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार ने हाईकोर्ट से पांच साप्ताह का समय मांगा है। सोमवार को सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि बाल संरक्षण आयोग और सीडब्ल्यूसी के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया लाभग पूरी कर ली गयी है। मुख्यमंत्री से मंजूरी लेकर इसे निर्वाचन आयोग के पास भेजा जायेगा। इस पूरी प्रक्रिया में पांच साप्ताह का समय लग जायेगा। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई पांच साप्ताह बाद निर्धारित कर दी।

झारखण्ड के रिक्त पदो



आपकी बहू हूं, पार्टी की प्रतिष्ठा रखने देहरी से बाहर रखा कदम, आशीर्वाद दें : पूर्णिमा

■ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और बुजुर्जों से खिल कर निया जाता का आशीर्वाद

■ कठा, भाजपा सांघ एण्डाईर की सरकार बनने से ही होगा झारखंड का समृद्धि विकास



खबर मन्त्र व्यूप्ते

जमशेदपुर। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी अपने चरम पर पहुंच चुकी है, और इस चुनावी समर में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से भाजपा की प्रत्याशी पूर्णिमा दास का अभियान उत्साह और उम्मीद से लंबे जारी है। भाजपा के संस्कार और संगठनात्मक स्तर से विरुद्ध पूर्णिमा दास का समर्थन कराया। यह विहंगम योग विश्वासीत वैदिक महायज्ञ संपन्न कराया। यह विहंगम योग के पुरोहित महावीर विद्यार्थी ने कराया, जिसमें यजमान रसायन पूर्व विधायक गुरुवरान् नायक स्पष्टीकरण एवं मानीलाल दास परिवार के संग दक्षिण झारखंड के महावीर विद्यार्थी प्रभार मंत्री मनमोहन महतो, परिचयी सिंहभूम के परामर्शक महेश निषाद, जिला के प्रमुख संयोजक बसंत महतो, संयोजक अवधेश कुमार, मझगांव के प्रभारी रामपति उराव, खुटपानी के प्रभारी छोटेलाल, युवा प्रभारी प्रेम नायक भी शामिल थे।

ई-विजिल एप पर कर्ते आचार सहित उल्लंघन की शिकायत

जमशेदपुर। विधानसभा चुनाव 2024 में संतरं, नियक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने में आयोग के साथ साथ मतदाताओं की भी सजग भूमिका जरूरी है। जब तक मतदाता चुनाव में प्रलोभन देने के हथकंठों को आख बढ़ करके यू-ही देखते रहेंगे, तब तक इस पर सांकेतिक लागतों से बचना चाहिए। इसके लिए चुनाव आयोग ने तकनीक का इस्तेमाल करते हुए C-Vigil ऐपलाइन एप मतदाताओं के लिए बनाया है श्री मितल ने बताया कि सी-विजिल एप के माध्यम से आम मतदाता अदर्श चुनाव आयोर सहित के उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं।

आइएसएल : लोकतंत्र की धून पर झूमे लोग

